

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2359 वर्ष 2020

बुलेवर्ड एंटरप्राइजेज अपने साझेदार अर्थात् संदीप मुरारका के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम
3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0-सह-वरीय अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री रवि प्रकाश मिश्रा, ए0ए0जी0-II के ए0सी0

04/04.01.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव, 2019 के दौरान स्टेशनरी/प्रिंटिंग सामग्री की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के फर्म को उपयुक्त ब्याज के साथ बिल की देय राशि का भुगतान करने के लिए उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, उत्तरदाता संख्या 2 पर निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई क्योंकि याचिकाकर्ता को उसके लिए केवल आंशिक भुगतान किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी सं० 2 के हस्ताक्षर के तहत जारी ज्ञापन सं० 1998/जमशेदपुर दिनांक 30 सितंबर, 2019 (वर्तमान रिट याचिका के अनुलग्नक-1) में निहित "बहुत संक्षिप्त निविदा सूचना" के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने उसी में भाग लिया और उक्त निविदा में सफल घोषित होने के बाद, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्टेशनरी/मुद्रण सामग्री की आपूर्ति के लिए काम दिया गया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहा है कि निविदा सूचना की आवश्यकता के अनुसार उक्त सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद, इसने 1,42,39,401/- ₹0 का बिल प्रस्तुत किया, जिसमें से उत्तरदाताओं ने भुगतान की सीमा 1,30,56,260/- ₹0 तक स्वीकार किया। हालांकि उक्त राशि में से, उसी का 40 प्रतिशत यानी 52,22,504/- ₹0 प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश के अनुसार अवैध रूप से काटा गया है, जैसा कि 29 फरवरी, 2020 को उप चुनाव अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा हस्ताक्षरित बिल के निष्कर्ष से स्पष्ट होगा (जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर अपने आवेदन पर प्रस्तुत की गई थी) और अंतिम देय राशि 75,23,538/- ₹0 तक आ गई।

उत्तरदाताओं की उक्त कार्यवाही से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष कई अभ्यावेदन दिये (जिसकी प्रतियां वर्तमान रिट याचिका के लिए अनुबंध-7 श्रृंखला के रूप में संलग्न की गई हैं)। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 ने 40 प्रतिशत कटौती बिल राशि जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री रवि प्रकाश मिश्रा, ए0ए0जी0-II के ए0सी0 उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए और निवेदन किए कि चूंकि वर्तमान मामले को तथ्यात्मक रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है, यदि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन देता है, तो उक्त प्रतिवादी द्वारा एक उचित सूचित निर्णय लिया जाएगा।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नए अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2, उक्त अभ्यावेदन दाखिल होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उचित सूचित निर्णय लेगा।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)